आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार एकांश

देहरादून (उत्तराखण्ड)

गुरूवार 03.09.2026

समय1305

मुख्य समाचार:-

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सिल्क एक्सपो-2026 का शुभारंभ किया।
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में अब तक राज्य के 452 मदरसों में से 200 मदरसो ने मान्यता के लिए आवेदन किए।
केंद्र सरकार ने पिछले पांच सालों में उत्तराखंड में 15 वाटरशेड परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की।
और.. हरिद्वार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था और भीड प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए मजिस्ट्रेटों की तमाती के आदेश जारी।

<u>सिल्क एक्सपो-2026</u>

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सिल्क एक्सपो-2026 का शुभारंभ किया। सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय रेशम बोर्ड, रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड और उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम 7 सितंबर तक चलेगा। इसमें देश के कई जिलों से कारीगर शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट -

सिल्क एक्सपो-2026 में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के 25 से ज्यादा प्रतिभागियों ने रेशमी उत्पादों का प्रदर्शन किया। यह मंच रेशम से जुड़े उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद

करेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य को देश में उच्च गुणवत्ता वाले बाईवोल्टाइन सिल्क के लिए खास पहचान मिली ह॥ श्री जोशी ने कि पिछले साल में राज्य में कुल 314.6 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले बाईवोल्टाइन रेशम कोयों का उत्पादन किया गया ह॥ राज्य में रेशम कीटपालन से लगभग साढ़े 10 हजार किसान परिवार जुड़े हैं, जो रेशम उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य ह□कि किसान केवल कच्चा माल बेचने तक सीमित न रहें, बल्कि मूल्य संवर्धन से होने वाली आय में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो।

अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

सरकार ने जुलाई में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया था। इसके गठन का उद्देश्य मदरसों को शिक्षा विभाग की मुख्यधारा से जोड़ना ह॥ राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि राज्य के 452 मदरसों में से करीब 200 मदरसे मान्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं और लगभग 60 मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही ह॥ श्री गांधी ने कहा कि प्राधिकरण बनने के बाद अब राज्य में संचालित मदरसों को राज्य शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। जो मदरसे मान्यता नहीं ले रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इंटीग्रेटिव मेडिसिन संगोष्ठी

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने कहा ह□कि एकीकृत चिकित्सा का उद्देश्य विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं ह॥ इसका उद्देश्य सभी चिकित्सा प्रणालियों की सामूहिक शक्ति का उपयोग करना ह॥ इससे रोगियों और पूरी मानवता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।राज्यपाल देहरादून स्थित लोक भवन में आयोजित इंटीग्रेटिव मेडिसिन

संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।संगोष्ठी का आयोजन हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने किया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

केंद्र सरकार ने पिछले पांच सालों में उत्तराखंड में 15 वाटरशेड परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की ह॥ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर राज्य में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के कार्यो में तेजी लाये जाने का अनुरोध किया। श्री चौहान ने पत्र में लिखा कि राज्य में साल 2021 से 2026 तक 15 वाटरशेड परियोजनाओं को स्वीकृति मिली ह॥ उन्होने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से करीब 0.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित किया जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत दो अरब बत्तीस करोड़ छब्बीस लाख ह॰ जिसमें केंद्रीय अंश दो अरब नौ करोड़ तीन लाख रूपए निर्धारित ह॥ राज्य को अब तक लगभग 1 अरब, 13 करोड़, 48 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी ह॥

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

हरिद्वार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था और भीड प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए मजिस्ट्रेटों की तज्ञाती के आदेश जारी।जन्माष्टमी के लिए मंदिरों में झांकियां सजाई जा रही हैं, देर रात तक पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा ह॥ जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी तज्ञात मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखें।

निरीक्षण

देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मसूरी के संवेदनशील क्षेत्रों का जायका लिया। जिलाधिकारी ने मसूरी के पानीवाला बैंड और ग्लोगी का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के माध्यम से मार्ग खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क पर 24 घंटे निगरानी रखने, नालियों और पुलियों की नियमित सफाई करने और चेतावनी बोर्ड लगाने के आदेश दिए गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही सुरक्षित रहे और पानी के तेज बहाव से सड़क को क्षति न पहुंचे। डॉ. आशीष चौहान ने लोक निर्माण विभाग को एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तय्यार करने को कहा जिससे बार-बार सड़क बंद होने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तय्यार करने के बाद पहाड़ी ढलानों, जमीन की मजबूती और जल निकासी का वज्ञानिक अध्ययन कर पक्के सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने जिला आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य

चम्पावत जिले के लोहाघाट में सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के उप जिला चिकित्सालय की टीम ने एक जटिल प्रसव को सफलतापूर्वक संपन्न कराते हुए मां और नवजात दोनों की जान बचाई है। उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विराज राठी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।